International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक एवं वैचारिक विस्तार में कल्याण सिंह की भूमिका: एक अध्ययन

सक्षम कुमार
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली (उ०प्र०)
ईमेल: kumarsaksham723@gmail.com
प्रोफेसर (डॉ०) मनमीत कौर
विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली (उ०प्र०)

शोध सार

उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उदय और उसके सामाजिक-राजनीतिक विस्तार का अध्ययन भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति की परिवर्तनशील प्रकृति को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक एवं वैचारिक विस्तार में कल्याण सिंह की भूमिका का विश्लेषण करना है। अध्ययन में विशेष रूप से 1980 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर समकालीन काल तक के राजनीतिक परिवर्तनों का परीक्षण किया गया है। इस अवधि में मण्डल राजनीति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राम जन्मभूमि आंदोलन तथा सामाजिक अभियांत्रिकी (Social Engineering) जैसी प्रक्रियाओं ने राज्य की राजनीतिक संरचना को व्यापक रूप से प्रभावित किया। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि कल्याण सिंह ने मण्डल और कमंडल के मध्य विद्यमान वैचारिक द्वंद्व को सामाजिक अभियांत्रिकी की रणनीति के माध्यम से राजनीतिक अवसर में रूपांतरित किया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक व्यापक सामाजिक गठबंधन स्थापित करने में सफल हुई। जून 1991 के विधानसभा चुनाव, राम जन्मभूमि आंदोलन, 6 दिसंबर 1992 की घटनाएँ तथा उनके प्रशासनिक निर्णयों का विश्लेषण यह संकेत देता है कि उनके नेतृत्व ने पार्टी की वैचारिक पहचान के साथ-साथ उसकी संगठनात्मक विश्वसनीयता को भी सुदृढ़ किया। इसके अतिरिक्त नकल विरोधी अधिनियम, किसान बही योजना, कानून-व्यवस्था में सुधार तथा संगठन के बूथ-स्तरीय विस्तार जैसे प्रशासनिक एवं सांगठनिक उपायों ने भारतीय जनता पार्टी की दीर्घकालिक राजनीतिक आधार-रचना को मजबूत किया। शोध का निष्कर्ष यह प्रतिपादित करता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक विस्तार, सामाजिक पुनर्संरचना तथा वैचारिक सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में कल्याण सिंह की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही। उनके द्वारा विकसित सामाजिक एवं संगठनात्मक मॉडल का प्रभाव राज्य की समकालीन राजनीति तथा भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान चुनावी रणनीतियों में भी परिलक्षित होता है।

बीज शब्द - कल्याण सिंह; भारतीय जनता पार्टी; उत्तर प्रदेश की राजनीति; सामाजिक अभियांत्रिकी; मण्डल राजनीति; कमंडल राजनीति; गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग; सांस्कृतिक राष्ट्रवाद; राम जन्मभूमि आंदोलन।

विषय प्रवेश एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

उत्तर प्रदेश भारतीय संघ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख शक्ति-केंद्र भी रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लगभग चार दशकों तक राज्य की राजनीतिक व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व में संचालित होती रही। राजनीतिक विज्ञान के विद्वान इस व्यवस्था को *एक-दलीय प्रभुत्व प्रणाली* (One-Party

Dominance System) के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें कांग्रेस ने एक व्यापक सामाजिक गठबंधन (Catch-all Party) के माध्यम से सवर्ण जातियों, मुस्लिम समुदाय तथा दलित वर्गों को अपने राजनीतिक आधार के रूप में संगठित रखा। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का दीर्घकालीन वर्चस्व स्थापित रहा। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में यह राजनीतिक संरचना क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरने लगी। कांग्रेस के भीतर बढ़ती गुटबाज़ी, प्रशासनिक शिथिलता, ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष तथा बदलते सामाजिक समीकरणों ने उसके पारंपरिक जनाधार को कमजोर किया। इस परिवर्तन ने राज्य की राजनीति में एक वैचारिक एवं संगठनात्मक रिक्तता उत्पन्न की, जिसके परिणामस्वरूप तीन प्रमुख राजनीतिक धाराएँ समानांतर रूप से उभरकर सामने आईं। प्रथम, मण्डल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक लामबंदी, जिसका नेतृत्व प्रारम्भ में जनता दल तथा बाद में समाजवादी पार्टी ने किया। द्वितीय, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में दलित राजनीतिक चेतना एवं प्रतिनिधित्व का विस्तार। तृतीय, भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से विकसित कमंडल राजनीति।

इसी राजनीतिक संक्रमण काल में कल्याण सिंह का उदय उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक निर्णायक घटना के रूप में सामने आया। उनका नेतृत्व केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक आधार, वैचारिक दिशा तथा संगठनात्मक संरचना को नए सिरे से परिभाषित किया। विशेषतः गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग, ग्रामीण समाज तथा कृषक समुदाय के बीच भाजपा की राजनीतिक स्वीकार्यता के विस्तार में उनकी भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही। इसी कारण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक एवं वैचारिक विस्तार के अध्ययन में कल्याण सिंह का राजनीतिक योगदान एक केंद्रीय विश्लेषणात्मक विषय के रूप में उभरता है।

जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक: सामाजिक एवं संगठनात्मक सीमाएँ

भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक एवं संगठनात्मक पृष्ठभूमि भारतीय जनसंघ (1951–1977) से जुड़ी रही है। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के उपरांत भी उत्तर प्रदेश में उसका राजनीतिक प्रभाव मुख्यतः शहरी क्षेत्रों, व्यापारी वर्ग तथा उच्च जातीय समुदायों तक सीमित रहा। प्रारम्भिक चरण में पार्टी ग्रामीण समाज, कृषक समुदाय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य व्यापक संगठनात्मक आधार विकसित करने में सफल नहीं हो सकी। क्रिस्टोफ़ जाफ़रलो तथा ज़ोया हसन सहित अनेक राजनीतिक विश्लेषकों ने इस अवधि में भाजपा की सीमाओं का उल्लेख करते हुए संकेत किया है कि उसका संगठन मुख्यतः शहरी केंद्रों तक सीमित था। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ तथा आगरा जैसे नगरों में उसका अपेक्षाकृत प्रभाव अवश्य था, किन्तु ग्रामीण उत्तर प्रदेश में उसकी उपस्थिति अत्यंत सीमित रही। इसी प्रकार नेतृत्व, प्रत्याशी चयन तथा संगठनात्मक संरचना में उच्च जातीय प्रतिनिधित्व की प्रधानता विद्यमान थी, जिसके कारण अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कृषक समुदाय के साथ पार्टी का सामाजिक संवाद अपेक्षाकृत कमजोर बना रहा। इस संगठनात्मक सीमा का प्रत्यक्ष प्रभाव चुनावी प्रदर्शन पर भी दिखाई देता है। वर्ष 1985 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 425 में से केवल 16 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। यह परिणाम स्पष्ट करता है कि उस समय पार्टी राज्य की मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में प्रभावी शक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो सकी थी। परिणामस्वरूप पार्टी नेतृत्व के समक्ष यह चुनौती थी कि वह अपनी पारंपरिक शहरी एवं सवर्ण छवि से आगे बढ़ते हुए ग्रामीण क्षेत्रों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच संगठनात्मक विस्तार सुनिश्चित करे।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

कल्याण सिंह का राजनीतिक उदय: सामाजिक पृष्ठभूमि और नेतृत्व निर्माण

कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के मढ़ौली ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ। वे अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोध-राजपूत समुदाय से संबंध रखते थे। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि तथा ग्रामीण परिवेश ने उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को प्रारम्भिक स्तर पर ही जनसामान्य से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका राजनीतिक जीवन किसी वंशानुगत परंपरा का परिणाम न होकर वैचारिक प्रतिबद्धता तथा संगठनात्मक सक्रियता पर आधारित था। किशोरावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के पश्चात उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर कार्य किया तथा 1967 में भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके पश्चात वे अनेक बार विधायक चुने गए तथा जनता पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। 1980 के दशक के मध्य में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में संगठन के सामाजिक विस्तार की रणनीति के अंतर्गत कल्याण सिंह को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। यह निर्णय केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं था, बल्कि भाजपा की सामाजिक संरचना के पुनर्गठन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण संगठनात्मक हस्तक्षेप था। एक पिछड़े वर्ग के प्रभावशाली नेता तथा अनुशासित संगठनकर्ता के रूप में कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण समाज, कृषक समुदाय तथा गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य नई राजनीतिक पहचान प्रदान की। उनकी प्रशासनिक दृढ़ता तथा जनसंपर्क क्षमता ने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के प्रमुख जननेता के रूप में स्थापित किया।

मण्डल आयोग का प्रभाव एवं उत्तर प्रदेश की राजनीति का जातिगत पुनर्संरचन

1990 का दशक भारतीय राजनीति के इतिहास में एक निर्णायक संक्रमणकाल के रूप में स्थापित है। इस अवधि में लिए गए नीतिगत निर्णयों ने न केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को परिवर्तित किया, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, चुनावी व्यवहार तथा सत्ता-साझेदारी के स्थापित प्रतिमानों को भी पुनर्परिभाषित किया। अगस्त 1990 में तत्कालीन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes—OBC) के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस निर्णय ने भारतीय राजनीति, विशेषकर उत्तर प्रदेश के सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव डाला। मण्डल आयोग के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर राजनीतिक चेतना और प्रतिनिधित्व की आकांक्षा तीव्र गति से विकसित हुई। जनता दल तथा उसके पश्चात समाजवादी पार्टी ने इस सामाजिक परिवर्तन को अपनी राजनीतिक रणनीति का आधार बनाया तथा पिछड़े वर्गों के राजनीतिक सशक्तीकरण को अपनी वैचारिक पहचान के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि इस प्रक्रिया ने व्यापक स्तर पर पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया, तथापि प्रारम्भिक चरण में इसका नेतृत्व मुख्यतः यादव समुदाय के इर्द-गिर्द केंद्रित होता गया। उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी लगभग 40 से 45 प्रतिशत के मध्य रही है। इस व्यापक सामाजिक समूह में यादव समुदाय के अतिरिक्त लोध, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, निषाद, कश्यप, बिंद, प्रजापति तथा गुर्जर जैसी अनेक प्रभावशाली एवं संख्यात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जातियाँ सम्मिलित थीं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर इन समुदायों के भीतर यह धारणा विकसित होने लगी कि मण्डल राजनीति का लाभ अपेक्षाकृत सीमित जातीय समूहों तक ही केंद्रित हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़ी जातियों की राजनीतिक भागीदारी अपेक्षित स्तर तक सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। दूसरी ओर, आरक्षण संबंधी निर्णयों के कारण सवर्ण समुदायों में असंतोष तथा राजनीतिक असुरक्षा की भावना भी तीव्र

हुई। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया वैचारिक एवं सामाजिक द्वंद्व उभरकर सामने आया, जिसे सामान्यतः 'मण्डल बनाम कमंडल' की राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यह केवल आरक्षण अथवा धार्मिक पहचान का प्रश्न नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा चुनावी पुनर्संरचना के मध्य विकसित हो रही नई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक था। इसी परिवर्तित राजनीतिक संदर्भ ने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष यह चुनौती प्रस्तुत की कि वह सामाजिक न्याय की राजनीति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए अपने राजनीतिक आधार का विस्तार किस प्रकार करे। यही वह ऐतिहासिक परिस्थिति थी, जिसमें कल्याण सिंह का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक महत्त्व प्राप्त करता है।

के. एन. गोविंदाचार्य एवं कल्याण सिंह का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल

मण्डल राजनीति के उभार ने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक जटिल राजनीतिक एवं वैचारिक चुनौती उत्पन्न कर दी। यदि पार्टी आरक्षण आधारित सामाजिक परिवर्तन का प्रत्यक्ष विरोध करती, तो उसके केवल उच्च जातीय समर्थन तक सीमित रह जाने की संभावना थी। इसके विपरीत यदि वह मण्डल राजनीति को बिना वैचारिक पुनर्संरचना के स्वीकार करती, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित उसकी मूल वैचारिक पहचान कमजोर पड़ सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने वैचारिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर एक वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति विकसित करने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के. एन. गोविंदाचार्य द्वारा प्रतिपादित 'सोशल इंजीनियरिंग' की अवधारणा विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस अवधारणा का मूल उद्देश्य जातीय आधार पर विभाजित सामाजिक समूहों को व्यापक सांस्कृतिक पहचान के अंतर्गत संगठित करना तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अपेक्षाकृत संतुलित मॉडल विकसित करना था। उत्तर प्रदेश में इस वैचारिक ढाँचे का सर्वाधिक प्रभावी राजनीतिक क्रियान्वयन कल्याण सिंह के नेतृत्व में दिखाई देता है।

कल्याण सिंह ने सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति को दो परस्पर पूरक आधारों पर विकसित किया। प्रथम, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक ऐसी व्यापक पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न जातीय समुदाय स्वयं को एक साझा सांस्कृतिक परंपरा का अंग अनुभव कर सकें। द्वितीय, संगठनात्मक संरचना तथा चुनावी प्रतिनिधित्व में अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेषकर गैर-यादव समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार वैचारिक एकता और सामाजिक प्रतिनिधित्व को परस्पर विरोधी न मानकर पूरक तत्वों के रूप में स्थापित किया गया। इस रणनीति का पहला प्रमुख आयाम राम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विस्तार था। कल्याण सिंह ने इस आंदोलन को केवल धार्मिक अभियान के रूप में प्रस्तुत करने के स्थान पर उसे व्यापक सांस्कृतिक अस्मिता तथा सामाजिक एकात्मता के प्रतीक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप विभिन्न जातीय समूहों के मध्य साझा राजनीतिक पहचान विकसित करने का आधार तैयार हुआ।

दूसरा महत्त्वपूर्ण आयाम संगठनात्मक लोकतंत्रीकरण था। प्रदेश संगठन, चुनावी प्रत्याशियों के चयन तथा राजनीतिक नेतृत्व के निर्माण में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए। इससे भारतीय जनता पार्टी का संगठन पारंपरिक उच्च जातीय नेतृत्व की सीमाओं से बाहर निकलकर अधिक व्यापक सामाजिक स्वरूप ग्रहण करने लगा। तीसरा आयाम स्वयं कल्याण सिंह के नेतृत्व से जुड़ा था। एक लोध-राजपूत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में उनकी सामाजिक पहचान ने गैर-यादव पिछड़े वर्गों के बीच भाजपा की स्वीकार्यता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं को ऐसे नेतृत्व के रूप में स्थापित किया, जो एक ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक प्रतिबद्धताओं के प्रति निष्ठावान था

और दूसरी ओर सामाजिक प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सहभागिता के प्रश्नों को भी समान महत्त्व देता था। यही कारण है कि सोशल इंजीनियरिंग की अवधारणा उत्तर प्रदेश में केवल वैचारिक विमर्श तक सीमित न रहकर एक प्रभावी चुनावी एवं संगठनात्मक रणनीति के रूप में विकसित हुई। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि के. एन. गोविंदाचार्य द्वारा प्रतिपादित सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत को उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक सफलता दिलाने का श्रेय प्रमुख रूप से कल्याण सिंह के नेतृत्व को जाता है। इस रणनीति ने भारतीय जनता पार्टी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व के मध्य संतुलन स्थापित करने का अवसर प्रदान किया, जिसने आगे चलकर राज्य में उसके सामाजिक विस्तार और चुनावी सफलता की आधारशिला रखी।

गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग की रणनीतिक राजनीतिक लामबंदी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक विस्तार का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आयाम गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग (Non-Yadav OBC) का राजनीतिक पुनर्संयोजन था। मण्डल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के पश्चात यद्यपि अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, तथापि इस वर्ग के भीतर यह धारणा भी विकसित हुई कि राजनीतिक नेतृत्व तथा सत्ता-साझेदारी का लाभ मुख्यतः यादव समुदाय के इर्द-गिर्द केंद्रित होता जा रहा है। इस परिस्थिति ने अन्य पिछड़ी जातियों के भीतर वैकल्पिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को बल प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसी सामाजिक-राजनीतिक अवसर को एक दीर्घकालिक संगठनात्मक रणनीति के रूप में रूपांतरित किया। कल्याण सिंह इस रणनीति के प्रमुख राजनीतिक आधार बने। अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेता होने के कारण उनकी सामाजिक विश्वसनीयता गैर-यादव समुदायों के मध्य अपेक्षाकृत अधिक थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए यह स्थापित करने का प्रयास किया कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद परस्पर विरोधी अवधारणाएँ नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक गठबंधन के पूरक आधार हो सकते हैं। इस प्रकार भाजपा ने पहली बार स्वयं को केवल उच्च जातीय राजनीतिक दल के रूप में प्रस्तुत करने के स्थान पर एक व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व वाले दल के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया।

क्रिस्टोफ़ जाफ़रलो की कृति *India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India* तथा ए. के. वर्मा के विभिन्न अध्ययनों में यह प्रतिपादित किया गया है कि उत्तर प्रदेश में गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग का भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव किसी आकस्मिक चुनावी घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित संगठनात्मक एवं सामाजिक रणनीति का प्रतिफल था। इन अध्ययनों के अनुसार भाजपा ने उन जातीय समूहों के मध्य राजनीतिक संवाद स्थापित किया, जो स्वयं को पिछड़ा वर्ग की राजनीति में अपेक्षित प्रतिनिधित्व से वंचित अनुभव कर रहे थे। कल्याण सिंह ने इस सामाजिक विस्तार की प्रक्रिया को केवल वैचारिक अपील तक सीमित नहीं रखा, बल्कि विभिन्न जातीय समूहों को संगठनात्मक भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया। विशेष रूप से लोध-राजपूत समुदाय, जिससे स्वयं कल्याण सिंह संबंध रखते थे, पश्चिमी, मध्य तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठित एवं स्थायी जनाधार बन गया। अलीगढ़, एटा, बुलन्दशहर, पीलीभीत, झाँसी तथा हमीरपुर जैसे जनपदों में इस सामाजिक आधार का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इसी प्रकार कुर्मी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा तथा अन्य कृषक समुदायों को भी संगठनात्मक स्तर पर पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए। संतोष गंगवार, ओम प्रकाश सिंह तथा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की सक्रिय राजनीतिक भूमिका ने इन समुदायों में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाने में योगदान दिया। इससे यह संदेश गया कि पार्टी केवल वैचारिक मंच नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व का भी अवसर प्रदान करने वाली राजनीतिक

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

संस्था है। अति-पिछड़ी एवं परंपरागत शिल्पकार जातियों—जैसे निषाद, मल्लाह, कश्यप, बिंद, प्रजापति तथा पाल समुदाय—को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक रणनीति में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन के सांस्कृतिक प्रतीकों, स्थानीय धार्मिक परंपराओं तथा सामाजिक सहभागिता के माध्यम से इन समुदायों को व्यापक हिंदू सामाजिक पहचान के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। इस प्रक्रिया ने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव अपनी पुस्तक *At the Heart of Power: The Chief Ministers of Uttar Pradesh* (2025) में उल्लेख करते हैं कि कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक भाषा को केवल शहरी मध्यवर्गीय विमर्श तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे ग्रामीण समाज, कृषक समुदाय तथा सामाजिक रूप से वंचित समूहों की आकांक्षाओं से जोड़ने का प्रयास किया। इस दृष्टि से उनका नेतृत्व भाजपा के सामाजिक पुनर्गठन की प्रक्रिया में एक निर्णायक कारक सिद्ध हुआ।

सवर्ण–पिछड़ा सामाजिक गठबंधन: भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक विस्तार का आधार

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि उसने सामाजिक विस्तार की प्रक्रिया में अपने पारंपरिक सवर्ण जनाधार को बनाए रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के नए सामाजिक समूहों को भी अपने साथ जोड़ा। सामान्यतः भारतीय राजनीति में किसी नए सामाजिक वर्ग को जोड़ने की प्रक्रिया पुराने समर्थन आधार के क्षरण का कारण बनती है, किन्तु कल्याण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती से सफलतापूर्वक उबरती दिखाई देती है। इस सामाजिक गठबंधन का प्रथम आधार साझा राजनीतिक विमर्श का निर्माण था। कांग्रेस की तुष्टिकरण संबंधी नीतियों तथा समाजवादी राजनीति की जाति-आधारित लामबंदी को भाजपा ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप सवर्ण तथा गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग दोनों के मध्य यह धारणा विकसित की गई कि स्थिर शासन, प्रशासनिक दृढ़ता तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी एक उपयुक्त राजनीतिक विकल्प है।

द्वितीय आधार राम जन्मभूमि आंदोलन की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता थी। 1989 से 1991 के मध्य आयोजित रामशिला पूजन, जनसभाओं तथा कारसेवा जैसे कार्यक्रमों ने विभिन्न जातीय समुदायों को एक साझा सांस्कृतिक मंच पर संगठित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर सवर्ण एवं पिछड़े वर्गों के युवाओं की संयुक्त सहभागिता ने इस आंदोलन को केवल धार्मिक अभियान तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सामाजिक एकात्मता एवं राजनीतिक लामबंदी के माध्यम के रूप में भी स्थापित किया। कल्याण सिंह ने इस सामाजिक ऊर्जा को प्रभावी चुनावी समर्थन में रूपांतरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तृतीय आधार संगठनात्मक संतुलन था। मुख्यमंत्री तथा प्रदेश नेतृत्व के रूप में कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। एक ओर उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व को राजनीतिक मुख्यधारा में स्थान दिया, वहीं दूसरी ओर कलराज मिश्र, केशरी नाथ त्रिपाठी, हुकुम सिंह तथा बालेश्वर त्यागी जैसे वरिष्ठ सवर्ण नेताओं को संगठन एवं शासन में प्रभावशाली दायित्व प्रदान किए। इससे पार्टी के भीतर सामाजिक समावेशन तथा नेतृत्व संतुलन दोनों को संस्थागत स्वरूप प्राप्त हुआ। बालेश्वर त्यागी ने अपनी पुस्तक *कल्याण सिंह: व्यक्तित्व एवं विचार* (1998) में उल्लेख किया है कि कल्याण सिंह का नेतृत्व किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि वे स्वयं को व्यापक सामाजिक हितों के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने में सफल रहे। यही कारण था कि ग्रामीण किसान, अन्य पिछड़ा वर्ग, शहरी मध्यमवर्ग तथा पारंपरिक सवर्ण मतदाता—सभी वर्गों में उनके प्रति राजनीतिक विश्वास का निर्माण हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि सवर्ण–पिछड़ा सामाजिक गठबंधन केवल चुनावी रणनीति नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की दीर्घकालिक सामाजिक पुनर्संरचना का आधार था। इस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा को एक सीमित

सामाजिक आधार वाले दल से व्यापक जनाधार वाले राजनीतिक संगठन के रूप में विकसित करने में निर्णायक योगदान दिया तथा आगे चलकर 1991 के विधानसभा चुनावों में उसकी ऐतिहासिक सफलता की आधारशिला तैयार की।

सांख्यिकीय एवं चुनावी विश्लेषण: 1985 से 1991 के मध्य भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विस्तार

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक एवं सांगठनिक विस्तार का सर्वाधिक प्रामाणिक आकलन विधानसभा चुनावों के सांख्यिकीय परिणामों के माध्यम से किया जा सकता है। 1985 से 1991 के मध्य हुए तीन विधानसभा चुनाव न केवल भाजपा की चुनावी प्रगति को प्रतिबिंबित करते हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक अभियांत्रिकी, गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक लामबंदी तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित रणनीति ने पार्टी के जनाधार को किस प्रकार परिवर्तित किया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन (1985–1991)

चुनाव वर्ष	भाजपा की सीटें	मत प्रतिशत	प्रमुख राजनीतिक विशेषता
1985	16	9.87%	सीमित शहरी प्रभाव एवं पारंपरिक सवर्ण जनाधार
1989	57	11.61%	राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक विस्तार
1991	221	31.45%	सवर्ण–गैर-यादव OBC सामाजिक गठबंधन के आधार पर पूर्ण बहुमत

स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India), उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन आँकड़े।

उपर्युक्त आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि वर्ष 1985 में भारतीय जनता पार्टी अभी उत्तर प्रदेश की मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में सीमित प्रभाव वाली पार्टी थी। 425 सदस्यीय विधानसभा में केवल 16 सीटों की प्राप्ति तथा 9.87 प्रतिशत मत-प्रतिशत इस तथ्य का संकेत देते हैं कि उस समय पार्टी का राजनीतिक प्रभाव मुख्यतः शहरी क्षेत्रों, व्यापारी वर्ग तथा उच्च जातीय मतदाताओं तक सीमित था। ग्रामीण क्षेत्रों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में उसका संगठनात्मक आधार अपेक्षाकृत कमजोर बना हुआ था। वर्ष 1989 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देता है। पार्टी की सीटें बढ़कर 57 हो गईं तथा मत-प्रतिशत 11.61 प्रतिशत तक पहुँच गया। यह वृद्धि केवल चुनावी संयोग नहीं थी, बल्कि राम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से विकसित हो रही सांस्कृतिक राजनीतिक चेतना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संगठनात्मक विस्तार का प्रारम्भिक परिणाम थी। इस चरण में भाजपा ने पहली बार पारंपरिक शहरी सीमाओं से बाहर निकलकर अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करानी प्रारम्भ की। वर्ष 1991 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इस चुनाव में पार्टी ने 221 सीटें प्राप्त कर पूर्ण बहुमत हासिल किया तथा उसका मत-प्रतिशत बढ़कर 31.45 प्रतिशत तक पहुँच गया। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक गठबंधन की नई संरचना के निर्माण का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। सवर्ण मतदाताओं के पारंपरिक समर्थन के साथ-साथ गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग, ग्रामीण समाज तथा नवगठित सांस्कृतिक राष्ट्रवादी मतदाता समूहों के समर्थन ने भाजपा को अभूतपूर्व चुनावी सफलता प्रदान

की। राजनीतिक दृष्टि से यह परिवर्तन केवल मत-प्रतिशत अथवा सीटों की वृद्धि तक सीमित नहीं था। यह भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक आधार के गुणात्मक विस्तार का संकेतक भी था। 1985 से 1991 के मध्य पार्टी ने स्वयं को एक सीमित शहरी दल से व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व वाले राजनीतिक संगठन के रूप में रूपांतरित किया। इस परिवर्तन में कल्याण सिंह की राजनीतिक स्वीकार्यता, संगठनात्मक नेतृत्व तथा सामाजिक अभियांत्रिकी की रणनीति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनावी आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन यह भी संकेत करता है कि इस अवधि में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता केवल राम जन्मभूमि आंदोलन की भावनात्मक अपील का परिणाम नहीं थी। यदि ऐसा होता, तो मत-प्रतिशत एवं सीटों में इस स्तर की व्यापक वृद्धि संभव नहीं होती। वस्तुतः यह परिणाम सामाजिक प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक विस्तार, वैचारिक स्पष्टता तथा प्रभावी नेतृत्व के सम्मिलित प्रभाव का द्योतक था। इस प्रकार चुनावी आँकड़े यह प्रमाणित करते हैं कि 1991 की सफलता के पीछे सामाजिक अभियांत्रिकी की रणनीति तथा कल्याण सिंह का नेतृत्व केंद्रीय कारक के रूप में उपस्थित था। के. एन. गोविंदाचार्य द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अभियांत्रिकी की अवधारणा को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहारिक रूप प्रदान करने में कल्याण सिंह की भूमिका निर्णायक रही। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को व्यापक सामाजिक पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हुए गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक रणनीति का अभिन्न अंग बनाया। परिणामस्वरूप भाजपा का सामाजिक आधार उल्लेखनीय रूप से विस्तृत हुआ तथा वह उच्च जातीय समर्थन तक सीमित राजनीतिक दल की छवि से बाहर निकल सकी। चुनावी आँकड़ों, समकालीन राजनीतिक अध्ययनों तथा उपलब्ध साहित्य के तुलनात्मक विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कल्याण सिंह का योगदान केवल एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अथवा संगठनकर्ता तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक आधार के पुनर्गठन, नेतृत्व के विकेंद्रीकरण तथा वैचारिक विस्तार को ऐसी दिशा प्रदान की, जिसने आगे चलकर उत्तर प्रदेश में पार्टी की दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता को सुदृढ़ किया। अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक एवं वैचारिक विस्तार के अध्ययन में कल्याण सिंह की भूमिका एक केंद्रीय विश्लेषणात्मक तत्व के रूप में स्थापित होती है। उनके नेतृत्व में विकसित सामाजिक अभियांत्रिकी का मॉडल भारतीय राजनीति में सामाजिक गठबंधन निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है, जिसकी प्रासंगिकता समकालीन राजनीतिक विमर्श में भी बनी हुई है।

राम जन्मभूमि आंदोलन का राजनीतिक चेहरा एवं जून 1991 का ऐतिहासिक बहुमत

1980 के दशक के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश की राजनीति एक व्यापक वैचारिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। इस अवधि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), विश्व हिंदू परिषद (VHP) तथा अन्य संबद्ध संगठनों के नेतृत्व में संचालित राम जन्मभूमि आंदोलन धार्मिक विवाद की सीमाओं से आगे बढ़कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऐतिहासिक स्मृति तथा बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक अस्मिता के प्रमुख राजनीतिक विमर्श के रूप में उभरा। इस आंदोलन ने उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश, में राजनीतिक चेतना के पुनर्संरचना की प्रक्रिया को गति प्रदान की। सितंबर 1990 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई राम रथ यात्रा ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यात्रा के दौरान तथा उसके पश्चात अयोध्या में कारसेवा को लेकर उत्पन्न परिस्थितियों, विशेषतः 30 अक्टूबर एवं 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा कारसेवकों पर की गई पुलिस कार्रवाई, ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक वातावरण को अत्यंत संवेदनशील बना दिया। इन घटनाओं ने जनभावनाओं, राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा चुनावी व्यवहार पर व्यापक प्रभाव डाला।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष यह चुनौती थी कि सांस्कृतिक आंदोलन को लोकतांत्रिक राजनीति के प्रभावी जनसमर्थन में किस प्रकार रूपांतरित किया जाए। इस संदर्भ में कल्याण सिंह का नेतृत्व निर्णायक रूप से उभरकर सामने आया। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को केवल धार्मिक आस्था का प्रश्न न मानते हुए उसे ग्रामीण समाज, किसान, सामान्य नागरिक तथा व्यापक सामाजिक सम्मान के विमर्श से जोड़ने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप राम जन्मभूमि आंदोलन का राजनीतिक आधार शहरी सीमाओं से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तृत हुआ। समकालीन वैचारिक साहित्य, विशेषतः *पांचजन्य* तथा *ऑर्गनाइज़र* के 1990–1991 के अंकों का विश्लेषण यह संकेत करता है कि कल्याण सिंह को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता के प्रतिनिधि नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुतीकरण ने उन्हें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जननेता के रूप में स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जून 1991 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव: जन-आंदोलन से चुनावी वैधता तक

जून 1991 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का सूचक सिद्ध हुआ। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का अवसर नहीं था, बल्कि दो भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों—मण्डल आधारित सामाजिक प्रतिनिधित्व तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद—के मध्य लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख मंच भी था। भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सुशासन तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व को अपनी चुनावी रणनीति का आधार बनाया। चुनाव प्रचार के दौरान कल्याण सिंह ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जनसभाएँ आयोजित कीं। उनकी राजनीतिक शैली का प्रमुख गुण यह था कि वे जटिल वैचारिक प्रश्नों को सरल, सहज एवं लोकभाषा में प्रस्तुत करते थे। उनके भाषणों में सांस्कृतिक पहचान, सुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार-मुक्त शासन की अवधारणाएँ समान रूप से उपस्थित रहती थीं। इस कारण उनकी अपील केवल वैचारिक समर्थकों तक सीमित न रहकर ग्रामीण एवं सामान्य मतदाताओं तक भी प्रभावी रूप से पहुँची। भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 1991 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 425 सदस्यीय विधानसभा में 221 सीटें प्राप्त कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। इसी अवधि में पार्टी का मत-प्रतिशत 1989 के 11.61 प्रतिशत से बढ़कर 31.45 प्रतिशत हो गया, जो लगभग 19.84 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसके विपरीत जनता दल तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के मत-प्रतिशत एवं सीटों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। यह परिणाम स्पष्ट संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पारंपरिक सवर्ण मतदाताओं के अतिरिक्त गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ग्रामीण समाज के व्यापक वर्गों का समर्थन भी प्राप्त किया।

यह चुनावी सफलता केवल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावनात्मक अपील का परिणाम नहीं थी, बल्कि सामाजिक अभियांत्रिकी, संगठनात्मक विस्तार, प्रभावी नेतृत्व तथा व्यापक राजनीतिक संवाद के संयुक्त प्रभाव का प्रतिफल थी। इस दृष्टि से जून 1991 का चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक एवं राजनीतिक पुनर्संरचना का निर्णायक चरण माना जा सकता है।

6 दिसंबर 1992 का घटनाक्रम, संवैधानिक दायित्व एवं वैचारिक प्रतिबद्धता

6 दिसंबर 1992 की घटना स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एवं संवैधानिक इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। जून 1991 में गठित भारतीय जनता पार्टी सरकार के समक्ष एक ओर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी व्यापक जन-भावनाएँ थीं, तो दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय, संविधान तथा विधि-व्यवस्था के संरक्षण का दायित्व भी था। 6 दिसंबर 1992 को प्रस्तावित कारसेवा के दौरान अयोध्या में लाखों कारसेवकों की उपस्थिति ने राज्य सरकार के समक्ष अभूतपूर्व प्रशासनिक चुनौती उत्पन्न कर दी।

गोली न चलाने का निर्णय: प्रशासनिक विवेक और मानवीय दृष्टिकोण

घटनाक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बल-प्रयोग की संभावना पर विचार किए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कारसेवकों पर गोली न चलाने का निर्णय लिया। उपलब्ध प्रशासनिक विवरणों के अनुसार इस निर्णय का आधार व्यापक जन-हानि, संभावित सांप्रदायिक हिंसा तथा 1990 की गोलीबारी जैसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति से बचना था। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल स्वरूप ने भी अपने संस्मरणों में इस निर्णय को प्रशासनिक विवेक तथा मानवीय दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण बताया है। विवादित ढाँचे के ध्वंस के पश्चात कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से तत्काल त्यागपत्र देकर घटना की नैतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी स्वीकार की। इसके उपरांत केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना संबंधी कार्यवाही में भी उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया और दंड को स्वीकार किया। इस घटनाक्रम ने उनके नेतृत्व की संवैधानिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में व्यापक चर्चा को जन्म दिया।

राजनीतिक प्रभाव एवं वैचारिक विरासत

6 दिसंबर 1992 के पश्चात कल्याण सिंह की राजनीतिक पहचान भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख वैचारिक नेता के रूप में और अधिक सुदृढ़ हुई। समकालीन राजनीतिक साहित्य, पार्टी अभिलेखों तथा पत्रकारिता संबंधी स्रोतों में उनके त्यागपत्र को वैचारिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक उत्तरदायित्व के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 1993 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मत-प्रतिशत लगभग 33.3 प्रतिशत तक पहुँचना इस बात का संकेत देता है कि इस घटनाक्रम के बावजूद पार्टी का सामाजिक आधार बना रहा तथा उसका राजनीतिक प्रभाव कायम रहा। उपलब्ध प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 6 दिसंबर 1992 का घटनाक्रम कल्याण सिंह के राजनीतिक जीवन का सबसे निर्णायक चरण था। उनके प्रशासनिक निर्णय, नैतिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति तथा त्यागपत्र ने भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक विमर्श और संगठनात्मक राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला। इस दृष्टि से यह घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति, संवैधानिक उत्तरदायित्व तथा भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक विकास के अध्ययन में एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में स्थापित होती है।

प्रशासनिक मॉडल, सुशासन एवं सुदृढ़ राज्य की अवधारणा

मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल (1991–1992 एवं 1997–1999) में कल्याण सिंह ने प्रशासनिक अनुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व पर आधारित शासन व्यवस्था को प्राथमिकता दी। उनकी प्रशासनिक नीति का प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार, अपराध एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप को नियंत्रित करते हुए प्रभावी सुशासन स्थापित करना था। इस संदर्भ में उनका प्रशासनिक मॉडल *स्ट्रॉन्ग स्टेट* (Strong State) की अवधारणा के निकट माना जाता है।

नकल विरोधी अधिनियम, 1992

कल्याण सिंह सरकार ने **उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992** लागू कर परीक्षा प्रणाली में व्याप्त संगठित नकल पर नियंत्रण का प्रयास किया। इस अधिनियम के अंतर्गत नकल एवं नकल कराने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इस निर्णय ने शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन स्थापित करने तथा शासन की कठोर प्रशासनिक छवि को सुदृढ़ किया।

किसान बही योजना एवं राजस्व सुधार

ग्रामीण प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से **'किसान बही' योजना** प्रारम्भ की गई। इसके अंतर्गत किसानों को उनकी भूमि का आधिकारिक अभिलेख उपलब्ध कराया गया, जिससे बैंक ऋण प्राप्त करने, भूमि संबंधी कार्यों तथा राजस्व प्रक्रियाओं में सुविधा हुई। इस पहल का उद्देश्य भूमि अभिलेख प्रणाली को अधिक उत्तरदायी एवं किसान-केंद्रित बनाना था।

कानून-व्यवस्था एवं प्रशासनिक सुधार

कल्याण सिंह सरकार ने संगठित अपराध पर नियंत्रण तथा प्रशासनिक जवाबदेही को प्राथमिकता दी। अधिकारियों के स्थानांतरण को प्रशासनिक आवश्यकता तक सीमित करने तथा कानून-व्यवस्था के मामलों में प्रशासनिक तंत्र को अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया। इन कदमों का उद्देश्य शासन-प्रणाली में स्थिरता एवं दक्षता सुनिश्चित करना था।

सांगठनिक विस्तार, कैडर निर्माण एवं दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव

कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जिला स्तर से आगे बढ़ाकर बूथ स्तर तक सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया। संगठन के विस्तार, कार्यकर्ता-आधारित संरचना तथा वैचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की संगठनात्मक पहुँच को मजबूत किया। इस प्रक्रिया ने भाजपा के स्थायी कैडर निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व का विकास

कल्याण सिंह के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं क्षेत्रों से अनेक नेताओं को संगठन और सरकार में अवसर मिला। उनके नेतृत्वकाल में राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र, संतोष गंगवार, ओम प्रकाश सिंह तथा अन्य नेताओं का राजनीतिक एवं संगठनात्मक विकास हुआ। इससे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अधिक व्यापक एवं समावेशी बना।

सांगठनिक प्रभाव एवं राजनीतिक परिवर्तन

1999 के बाद कल्याण सिंह के भाजपा से अलग होने की अवधि में उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की सीटों एवं मत-प्रतिशत में कमी देखी गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आधार को बनाए रखना पार्टी के लिए एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बन गया।

2014 के बाद भाजपा के पुनरुत्थान में प्रासंगिकता

2014 के लोकसभा चुनावों के पश्चात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पुनरुत्थान के संदर्भ में अनेक राजनीतिक विश्लेषकों ने गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग, सवर्ण एवं अन्य सामाजिक समूहों पर आधारित सामाजिक गठबंधन को महत्त्वपूर्ण कारक माना है। इस सामाजिक आधार की प्रारम्भिक संरचना को कल्याण सिंह के नेतृत्व में विकसित संगठनात्मक रणनीतियों से भी जोड़ा जाता है। समकालीन विश्लेषणों में उनके संगठनात्मक मॉडल को उत्तर प्रदेश में भाजपा के दीर्घकालिक विस्तार की आधारभूमि के रूप में देखा गया है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक एवं वैचारिक विस्तार की प्रक्रिया में कल्याण सिंह की भूमिका बहुआयामी एवं महत्त्वपूर्ण रही। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से 1990 के दशक तक राज्य की राजनीति में सामाजिक पुनर्संरचना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा संगठनात्मक विस्तार की जो प्रक्रियाएँ विकसित हुईं, उनमें कल्याण सिंह ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक सामाजिक आधार का विस्तार करने के लिए गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग को संगठन एवं नेतृत्व में प्रतिनिधित्व प्रदान करना एक महत्त्वपूर्ण

राजनीतिक रणनीति सिद्ध हुई। इस प्रक्रिया ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के सामाजिक आधार को व्यापक बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया तथा 1991 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित कीं।

राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक राजनीति के एक महत्त्वपूर्ण आयाम के रूप में उभरकर सामने आया। जून 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन तथा 6 दिसंबर 1992 की घटनाओं के दौरान लिए गए प्रशासनिक निर्णय उनके राजनीतिक जीवन के निर्णायक पड़ाव सिद्ध हुए। विवादित ढाँचे के ध्वंस के उपरांत मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने घटना की नैतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी स्वीकार की, जो भारतीय राजनीति के अध्ययन में एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ के रूप में देखा जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से नकल विरोधी अधिनियम, 1992, किसान बही योजना, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व पर बल देने वाली नीतियाँ उनके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों में सम्मिलित हैं। इन पहलों ने शासन की प्रभावशीलता तथा प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में उनकी कार्यशैली को विशिष्ट पहचान प्रदान की। सांगठनिक स्तर पर बूथ-आधारित संरचना, कार्यकर्ता-आधारित संगठन तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने की रणनीति ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दीर्घकालिक विस्तार की आधारभूमि तैयार की। उपलब्ध चुनावी आँकड़ों तथा समकालीन राजनीतिक अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि इन संगठनात्मक प्रयासों का प्रभाव आगामी वर्षों में भी परिलक्षित हुआ। समग्रतः यह अध्ययन स्थापित करता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विकास, सामाजिक विस्तार तथा वैचारिक सुदृढ़ीकरण के विश्लेषण में कल्याण सिंह की भूमिका को एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारक के रूप में देखा जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एंटी-कॉपीइंग एक्ट. (1992). *द उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेन्शन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 1992* (यू.पी. एक्ट संख्या 13, 1992). गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश.
2. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. (1985–2022). *उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स*. भारत निर्वाचन आयोग.
3. ऑर्गनाइज़र. (1991–1992). *आर्काइव्स ऑन उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स*. भारत प्रकाशन (दिल्ली) लिमिटेड.
4. उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली. (1991–1992). *ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स एंड डिबेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली*. गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश.
5. उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली. (1997–1999). *ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स एंड डिबेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली*. गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश.
6. उत्तर प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट. (1992). *इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट ऑन किसान बही स्कीम एंड लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन*. गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश.
7. कमल संदेश. (1991–1999). *विशेषांक एवं आधिकारिक लेख*. भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय कार्यालय.
8. गुहा, रामचंद्र. (2007). *इंडिया आफ्टर गांधी: द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी*. मैकमिलन.
9. जाफ़रलो, क्रिस्टोफ़. (2003). *इंडियाज साइलेंट रिवोल्यूशन: द राइज ऑफ द लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडिया*. हर्स्ट एंड कंपनी.
10. त्यागी, बालेश्वर. (1998). *कल्याण सिंह: व्यक्तित्व एवं विचार*. प्रभात प्रकाशन.

11.पांचजन्य. (1990–1993). *अयोध्या आंदोलन एवं सुशासन विशेषांक*. भारत प्रकाशन (दिल्ली) लिमिटेड.

12.पाई, सुधा. (2002). *दलित असर्शन एंड द अनफिनिश्ड डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन: द बहुजन समाज पार्टी इन उत्तर प्रदेश*. सेज पब्लिकेशन्स.

13.यादव, श्यामलाल. (2025). *एट द हार्ट ऑफ पावर: द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश*. रूपा पब्लिकेशन्स.

14.वर्मा, ए. के. (2001). डेवलपमेंट एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन उत्तर प्रदेश. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, *36*(9), 731–740.

15.वर्मा, ए. के. (2017). द 2017 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस: पोलराइजेशन, सोशल इंजीनियरिंग एंड गवर्नेंस. *अकादमिक जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस*, *12*(1), 45–58.

16.शास्त्री, एस. (2018). पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया: ए स्टडी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. *इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन*, *64*(2), 185–198.

17.स्वरूप, अनिल. (2021). *एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस*. प्रभात प्रकाशन.

18.हसन, ज़ोया. (1998). *क्वेस्ट फॉर पावर: ऑपोज़िशनल पॉलिटिक्स एंड पोस्ट-कांग्रेस पॉलिटिक्स इन उत्तर प्रदेश*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.